21102015-ls-ngp-04-new.qxd 10/21/2015 11:31 AM Page 1

और... एक शे'र

तुम न कहती थीं कि बहुत बोलता हूं मैं
लो एक तुम्हारे जाने से चुप हो गया हूं मैं
-अज्ञात

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

किसी एक विचार को जीवन का लक्ष्य बनाओ और उस पर चलते रहो, सफलता मिलेगी.
■ स्वामी विवेकानंद

संपादकीय

असहिष्णुता चिंताजनक लोकतंत्र के खिलाफ भी

इन दिनों भारतीय समाज में असहिष्णुता का जो वातावरण बन रहा है, वह चिंताजनक है. यह लोकतंत्र के खिलाफ भी है. हम यह तो मानते हैं कि तालिबान और आईएसआईएस असहिष्णुता और हिंसा की राह पर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने यहां बढ़ती असहिष्णुता पर अंकुश लगाने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखाई देती. ऐसे में हम उन दहशतगर्दों के खिलाफ किस मुंह से खड़े हो सकेंगे. हमारे समाज में सौहार्द्र पैदा करने वालों की तथा धार्मिक कट्टरता के खिलाफ व आडंबर के खिलाफ जनजागरण करने वालों की हत्या हो रही है, ऐसे लोगों पर हमले हो रहे हैं. किसी के चेहरे पर स्याही पोती जा रही है, तो कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार किया जा रहा है. पहले इस आधार पर लोगों को मारा गया कि उन्होंने अपनी पसंद से जीवनसाथी चुना था, फिर उन लोगों को काफिर करार दिया गया जो अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ प्यार करते हैं, फिर उन लड़कियों से बलात्कार किया गया जिन्होंने उनके मन मुताबिक कपड़े नहीं पहने थे और अब उन लोगों को मारा जा रहा है या उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिनकी खाने-पीने की आदतें समाजविशेष के एक हिस्से जैसी नहीं हैं. भारत में लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि देश के राष्ट्रपति को ऐसी सांप्रदायिकता को रोकने के लिए सरकार को दो-दो बार संकेतों में आगाह करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि विविधता, सहिष्णुता और बहुलता भारत के मूल्यों में शुमार है और उन्हें मिटने नहीं दिया जा सकता. हम सबको मिलजुल कर रहना होगा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना होगा. बढ़ती हुई असहिष्णुता और फासीवादी प्रवृत्ति हमारे समाज को गर्त में ही ले जाएगी. विरोध का मतलब किसी का अपमान नहीं, हम यह साधारण सी बात क्यों नहीं समझ पाते. भारतीय समाज के प्रति सदियों से धारणा है कि यह सहिष्णु समाज है. विडंबना ही है कि हम अपने समाज सुधारकों की सीख को आसानी से भुलाते चले जा रहे हैं. आखिर समाज के सहिष्णु ताने-बाने को तहस-नहस करने वालों के भीतर यह भरोसा कैसे जागता है कि वे कानून और संविधान से ऊपर हैं, वे अपराध करेंगे और सजा से बच जाएंगे? दरअसल, ऐसे असामाजिक तत्व सामाजिक समर्थन जुटाने में सफल हो जाते हैं, जो किसी समुदायविशेष या जातिविशेष का होता है. यदि इस असहिष्णुता पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गति तेज होगी. अब सरकार का दायित्व है कि वह जनता में विश्वास भरे कि वह सुरक्षित है और अपने मन की बात सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर सकती है. उसकी निजी स्वतंत्रता पर कट्टरवादियों का पहरा नहीं होगा. प्रत्येक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का भरोसा पैदा करना होगा. सरकार को जताना होगा कि वह कट्टरता के सख्त खिलाफ है. सरकार, असहिष्णुता और हिंसा के खिलाफ निर्णायक संकल्प दिखाए और उसके बढ़ते खतरे के निर्मूलन के लिए कदम उठाए. ■■

अष्टभुजाओंवाली

नवरात्रि पर्व का आज आठवां दिन आ चुका था. धूमधाम से मातारानी की स्थापना कर पूजा-पाठ करते सप्ताह कैसे बीत गया, पता ही न चला.

लघुकथा

उषा अग्रवाल 'पारस'

आज अष्टमीपूजा, कन्याभोज के साथ हवन पूजन कर मां को विदाई देनी थी. चारों तरफ काम फैला था. खाना बनानेवाली मिसराइन अभी तक नहीं आई थी. इतनी देर पश्चात उसके आने की अब उम्मीद भी नहीं थी. तभी झाड़ू-पोंछा और बर्तन करनेवाली महरी का लड़का खबर लेकर आया, "मां बीमार है, वो नहीं आएगी."

समय सरकता जा रहा था. काम कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा था. मेरी परेशानी देख पति, बेटा और बेटी तीनों सामने आ खड़े हुए. पूजा की तैयारी पति ने संभाल ली. साफ-सफाई तथा बाहर के काम की तैयारी बेटे ने ली. भोजन बनवाने व परोसने की पूरी जिम्मेदारी बेटी ने उठा ली.

कुछ ही देर में सारा काम शांतिपूर्वक सहजता से निपट गया. आरती घुमाते हुए मां की दप-दप करती मुस्कुराती नजरों से मेरी नजर टकराई तो मुझे महसूस हुआ, मैं भी अष्टभुजाओंवाली हो गई हूं. ■■

सरकारी पारदर्शिता पर पहरे

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

मोदी सरकार ने न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता का शंख बजाया है. विशेष रूप से न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है. यों संसद से पारित एक विधेयक के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका अधिक शक्तिशाली हो जाने के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में रद्द कर दिया. फिर भी नियुक्तियों में पारदर्शिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार जारी रखने की व्यवस्था कर दी है. यह आशाजनक पहल है. एक तरफ सरकार के प्रभावशाली नेता-मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं, लेकिन अपनी सत्ता के गलियारों में पारदर्शिता बढ़ने के बजाय घटने की स्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं. सच तो यह है कि केंद्र और कुछ प्रदेशों की भाजपाशासित सरकारों ने सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर ही जंजीर डाल दी है. पारदर्शिता की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर ही पहरे लगा दिए हैं. सबसे मजेदार स्थिति राजस्थान की है. सूचना के अधिकार के आंदोलन में राजस्थान अग्रणी रहा है. यही नहीं 1977-78 में भैरोसिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में सूचना के अधिकार की पहल हो गई थी. बाद में ईमानदार और सुशिक्षित समाजसेवी अरुणा राय के नेतृत्व में हजारों शिक्षित-अशिक्षित लोगों ने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी. इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार का कानून बना. लेकिन उसी राजस्थान में भाजपा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सत्ता में आने के बाद पिछले डेढ़ वर्षों में सूचना अधिकार आयुक्तों का दफ्तर ही सूना हो गया है और सूचना मांगने के सैकड़ों आवेदन फाइलों में धूल चाट रहे हैं. वजह यह है कि राज्य सूचना आयोग के लिए 10 आयुक्तों में से नौ स्थान महीनों से खाली पड़े हैं. सरकार की मंशा लगती है कि 'न रहेगा सुनने वाला आयुक्त, तो न होगी सुनवाई.'

जब मंत्रियों को ही किसी निर्णय के बाद सूचना पाने का अधिकार होगा तो सामान्य नागरिकों के लिए कितनी पारदर्शिता होगी?

सरकार द्वारा जारी अधिकृत आंकड़ों के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत आए करीब नौ लाख 62 हजार आवेदन फिलहाल विचाराधीन हैं. यह संख्या निरंतर बढ़ने वाली है. यों देश में इस अधिकार के प्रति जागरूकता का परिणाम है कि इन दस वर्षों में सूचना के अधिकार का उपयोग करने वाले नागरिकों की संख्या 80 लाख तक पहुंच गई है. दूसरी तरफ सरकारी नेताओं और अफसरों का कष्ट बढ़ता जा रहा है. वे सूचना को छिपाने, दबाने, आवेदन को विभिन्न विभागों में घुमाने के हथकंडे अपनाने लगे हैं. आलम तो यह है कि संबंधित मंत्रालयों के मंत्री या भाजपा के सांसदों को कई जानकारियां नहीं मिल पातीं.

सूचना-प्रसारण और वित्त मंत्री अरुण जेटली न्यायपालिका में पारदर्शिता की दुहाई दे रहे हैं. लेकिन उनके अपने मंत्री साथियों को मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची के प्रस्तावों का विस्तृत विवरण पहले नहीं मिल पाता? मोदी सरकार को अपनों से ही 'लीक' होने का खतरा लगता है. इसलिए बैठक में पहुंचने पर कई मंत्रियों को प्रस्तावों की पूरी जानकारी मिल पाती है. इसका नफा-नुकसान यह होता है कि बैठक में प्रधानमंत्री या उनके द्वारा अनुमति प्राप्त वरिष्ठ मंत्री ही विचाराधीन विषयों पर बोल पाते हैं. मंत्रियों को सुनने की सुविधा है. कार्यसूची के प्रस्तावों का विवरण पहले मिलने पर मंत्री पहले से सोच-समझकर कुछ राय दे सकते हैं अथवा सवाल कर सकते हैं अन्यथा कुछ मिनटों की बैठक में नए मुद्दों पर फटाफट अपनी राय कोई मंत्री कैसे दे सकता है. मनमोहन एवं अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और पं.नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कार्यसूची के प्रस्तावों के विवरण भेजे जाते रहे हैं ताकि वे बैठक में खुलकर अपनी राय व्यक्त कर सकें. जब मंत्रियों को ही किसी निर्णय के बाद सूचना पाने का अधिकार होगा तो सामान्य नागरिकों के लिए कितनी पारदर्शिता होगी?

लोकतांत्रिक प्रावधान यह है कि संसद या विधानसभाओं में विचार के लिए आने वाले महत्वपूर्ण प्रस्तावित विधेयकों-कानूनों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, ताकि कोई भी सामान्य नागरिक अपनी राय भिजवा सके. भाजपा सरकार आने के बाद आया घरेलू हिंसा रोकथाम विधेयक सीधे संसद में पेश हुआ. जबकि करोड़ों लोगों के सामान्य जीवन को कानूनी परिधि में लाने वाली व्यवस्था पर पहले सार्वजनिक बहस एवं राय की गुंजाइश होती है. यह तर्क भी दिया जा रहा है कि अब देश में 'डिजिटल क्रांति' हो गई है. इसलिए विभिन्न मंत्रालयों की सूचनाएं निविदाएं प्राप्ति से स्वीकृति तक की जानकारी नेट पर उपलब्ध की जा रही है. लेकिन असलियत यह है कि सरकारी मंत्रालयों के नेट सर्वर पर बोझ होने से दो-दो दिन तक संबंधित विभागों की सूचनाएं खुल ही नहीं पातीं. यही नहीं कुछ मंत्रालयों के अधिकारी बड़ी चतुराई से अंतिम समय में सूचनाएं वेबसाइट पर डालते हैं, ताकि कम लोगों तक जानकारी पहुंचे. इससे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की गुंजाइश बन जाती है. फिर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोग क्या प्रतिदिन सभी मंत्रालयों-विभागों की वेबसाइट की सार्वजनिक सूचनाएं देख सकते हैं? महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहले की तरह कम खर्च पर अखबारों में भी देने से क्या पारदर्शिता का अधिक लाभ नहीं मिल सकेगा? बहरहाल, लोकतंत्र में सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होने की अपेक्षा बढ़ती रहनी चाहिए. ■■

मुनव्वर राणा का दर्द और संघ परिवार की मुश्किल

पुण्य प्रसून वाजपेयी
कार्यकारी संपादक, आज तक

"आप सम्मान वापस लौटाने के अपने ऐलान को वापस तो लीजिए. एक संवाद तो बनाइए. सरकार की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सम्मान लौटाने को वापस लीजिए. देश में एक अच्छे माहौल की दिशा में यह बड़ा कदम होगा. आप पहले सम्मान लौटाने को वापस तो लीजिए. यहीं न्यूज चैनल की बहस के बीच में आप कह दीजिए. देश में बहुत सारे लोग देख रहे हैं. आप कहिए, इससे देश में अच्छा माहौल बनेगा."

19 अक्तूबर को आजतक पर हो रही बहस के बीच में जब संघ विचारक राकेश सिन्हा ने उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा से अकादमी सम्मान वापस लौटाने के ऐलान को वापस लेने की गुहार बार-बार लगाई, तब हो सकता है जो भी देख रहा हो उसके जहन में मेरी तरह ही यह सवाल जरूर उठा होगा कि चौबीस घंटे पहले ही तो मुनव्वर राणा ने एक दूसरे न्यूज चैनल पर बीच बहस में अकादमी सम्मान लौटाने का ऐलान किया था तो यही संघ विचारक बाकायदा पिल पड़े थे. न जाने कैसे कैसे आरोप किस किस तरह जड़ दिए. लेकिन महज चौबीस घंटे बाद ही संघ विचारक के मिजाज बदल गए तो क्यों बदल गए. क्योंकि अकादमी सम्मान लौटाने वालों को लेकर संघ परिवार ने इससे पहले हर किसी पर सीधे वार किए. यही हाल 18 अक्तूबर को उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा के साथ भी हुआ. लेकिन अंदरूनी सच यह है कि जैसे ही मुनव्वर राणा ने अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया, सरकार की घिग्गी बंध गई. संघ परिवार के गले में मुनव्वर का सम्मान लौटाना हड्डी फंसने सरीखा हो गया क्योंकि अकादमी सम्मान लौटाने वालों की फेहरिस्त में मुनव्वर राणा पहला नाम थे जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान देश में सत्ता परिवर्तन के बाद मिला. सीधे कहें तो मोदी सरकार के वक्त मिला.

मुनव्वर राणा के स्टूडियो से निकलते ही जब उनसे बातचीत शुरू हुई और संघ की मान-मनौव्वल पर पूछा तो उन्होंने तुरंत शायरी दाग दी, जब रुलाया है तो हंसने पर न मजबूर करो / रोज बीमार का नुस्खा नहीं बदला जाता. यह तो ठीक है मुनव्वर साहब लेकिन कल तक जो आपको लेकर चिल्ल पों कर रहे थे आज गुहार क्यों लगा रहे हैं. अरे हुजूर यह दौर प्रवक्ताओं का है, जिन्हें देश का ही इतिहास-भूगोल नहीं पता वह मेरा इतिहास कहां से जानेंगे. कोई इन्हें बताए तो फिर बोल बदल जाएंगे. यह जानते नहीं कि शायर किसी के कंधे के सहारे नहीं चलता. और मैं तो हर दिल अजीज रहा है क्योंकि मैं खिलंदड़ हूं. अब यह मेरे ऊपर सोनिया गांधी के ऊपर लिखी कविता का जिक्र कर मुझे कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. यह नहीं जानते कि मेरा तो काफी वक्त केशव कुंज (दिल्ली में संघ हेडक्वार्टर) में भी गुजरा. मैंने तो नमाज तक केशव कुंज में अदा की है. तरुण विजय मेरे अच्छे मित्र हैं. एक

यह दौर प्रवक्ताओं का है, जिन्हें देश का ही इतिहास-भूगोल नहीं पता वह मेरा इतिहास कहां से जानेंगे.

वक्त उनसे कुंभ के दौरान उनकी मां के साथ मुलाकात हो गई तो तभी से. एक वक्त तो आडवाणीजी से भी मुलाकात हुई. आडवाणी जी के कहने पर मैंने सिंधु नदी पर भी कविता लिखी. सिंधु नदी को मैंने मां कहकर संबोधित किया. यह नौसिखियों का दौर है इसलिए इन्हें हर शायरी के मायने समझाने पड़ते हैं. यह हर शायरी को किसी व्यक्ति या वक्त से जोड़कर अपनी सियासत को हवा देते रहते हैं. मैंने तो सोनिया पर लिखा, 'मैं तो भारत में मोहब्बत के लिए आई थी /कौन कहता है हुकूमत के लिए आई थी / नफरतों ने मेरे चेहरे का उजाला छीना / जो मेरे पास था वो चाहने वाला छीना.' शायर तो हर किसी पर लिखता है. जिस दिन दिल कहेगा उस दिन मोदीजी पर भी शायरी चलेगी. अब नई पीढ़ी के प्रवक्ता क्या जाने कि संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने मेरे ऊपर लिखा और कांग्रेस की पत्रिका में भी मेरी शायरी का जिक्र हो चुका है. फिर ऐसे वैसों के सम्मान वापस लौटाने के बाद कदम पीछे खींचने की गुहार का मतलब कुछ नहीं. इतिहास बदला नहीं जाता. रचा जाता है. यह समझ जब आ जाएगी, तब आ जाएगी. अभी तो इतना ही कि, ऐ अंधेरे! देख ले मुंह तेरा काला हो गया / मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया. ■■

क्या हम सब खुद भ्रष्ट नहीं हैं?

वेद प्रताप वैदिक
वरिष्ठ पत्रकार

दिल्ली देश का दिल है. इस दिल्ली में रिश्वतखोरी का यह जलवा है तो पूरे देश का हाल क्या होगा? एक प्रामाणिक संस्था के सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली के कम से कम एक तिहाई परिवारों ने पिछले साल रिश्वत दी

सरकार की कमजोरी तो स्पष्ट है लेकिन एक सवाल यह भी है कि लोग रिश्वत देते ही क्यों हैं? क्या हम खुद भ्रष्ट नहीं हैं?

है. अंदाज है कि कुल मिलाकर पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों ने रिश्वत में 2 अरब 29 करोड़ रु. दिए हैं. हर परिवार ने लगभग 2500 रु. की रिश्वत दी है. यह रिश्वत सबसे ज्यादा पुलिस व परमिट देनेवाले विभाग को दी जाती है.

यह सर्वेक्षण साधारण घरों का है. उन लोगों का नहीं है, जो करोड़ों-अरबों का व्यापार करते हैं या कारखाने चलाते हैं या व्यावसायिक कंपनियां चलाते हैं. दो-ढाई हजार रु. तो वे टिप्स में दे देते हैं. उनकी रिश्वत का आंकड़ा करोड़ों-अरबों में जाता है. जितनी रिश्वत पूरी दिल्ली देती है, उतनी एक पूंजीपति दे देता है. जितनी रिश्वत दिल्ली के सारे पुलिसवाले मिलकर नहीं खाते, उतनी एक अकेला नेता खा जाता है.

दुखद बात यह है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने डेढ़ साल होने को आया, लेकिन रिश्वतखोरी का आलम ज्यों का त्यों है. मोदी को लोगों ने इसीलिए आंख मींचकर वोट दिया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी लेकिन आम जनता जिससे त्रस्त है, उस भ्रष्टाचार में रत्तीभर भी कमी नहीं आई है. यह ठीक है कि मोदी के डर के मारे सरकार के मंत्री और बड़े अफसर जरा सावधान हैं और अभी तक उनका कोई मामला उजागर नहीं हुआ है लेकिन आम आदमी इस सरकार से निराश होता जा रहा है. दिल्ली की प्रादेशिक सरकार के बारे में इस सर्वेक्षण का कहना है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार घटा है लेकिन यह फर्क आम आदमी नहीं कर पाता है. उसके लिए सब सरकारी कर्मचारी एक-जैसे हैं. दिल्ली की जनता काफी जागरूक है. वह भी यदि रिश्वत देने के लिए मजबूर है तो छोटे-मोटे शहरों और गांवों की दुर्दशा का अंदाज हम लगा सकते हैं.

सरकार की कमजोरी तो स्पष्ट है लेकिन एक सवाल यह भी है कि लोग रिश्वत देते ही क्यों हैं? क्या हम खुद भ्रष्ट नहीं हैं? ज्यादातर लोग गलत काम करते हैं, गैरकानूनी काम करते हैं और लाइन तोड़कर अपना काम पहले करवाना चाहते हैं- इसीलिए रिश्वत देते हैं. मैंने जीवन में कभी एक पैसा भी रिश्वत नहीं दी और मेरा काम कभी रुका नहीं. जरूरी यह है कि लोग जरा लड़ने का माद्दा पैदा करें और जरा धीरज रखें तो पुलिस वालों, बाबुओं, नेताओं को रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ■■

नजर के पार

रेल नीर : बोतलबंद पानी का खेल

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

देश की महत्वपूर्ण रेलों में 'रेल नीर' आपूर्ति से जुटे भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के दौरान घोटाले में भी घोटाला सामने आया है. इस मामले में बरामद की गई 27 करोड़ की नगद धनराशि में 4 लाख रुपए के नोट जाली मिले हैं. इस मामले में सीबीआई ने आर.के. एसोसिएट्स और वृंदावन फूड प्रोडक्ट के मालिक श्याम बिहारी अग्रवाल और उनके पुत्र अभिषेक अग्रवाल को हिरासत में लिया है. साथ ही भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरसीटीसी) के अधिकारी संदीप सिलास और एम.एस. चालिया को भी गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के पद पर तैनात थे. इन्होंने कैटरिंग ठेकेदार अग्रवाल से सांठगांठ करके राजधानी और शताब्दी जैसी प्रमुख रेलों में रेल नीर की बजाय सस्ता बोतलबंद पानी एवं पाउच उपभोक्ताओं को बेचे.

भारत में पानी और पानी को शुद्ध करने के उपकरणों का बाजार लगातार फैल रहा है. देश में करीब 85 लाख परिवार जल शोधित (प्यूरीफायर) उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं. बोतल और पाउच में बंद पानी का भारत में एक हजार करोड़ का बाजार तैयार हो चुका है. इसमें हर साल 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो रही है. देश में इस पानी के करीब एक सौ ब्रांड देशव्यापी हैं और 1200 से भी ज्यादा बंद पानी के संयंत्र लगे हुए हैं. देश का हर बड़ा कारोबारी समूह इस व्यापार में

उतरने की तैयारी में है.

भारतीय रेल भी बोतल बंद पानी के कारोबार में शामिल है. इसकी सहायक संस्था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) 'रेल नीर' नाम से पानी का उत्पादन करती है. इसके लिए दिल्ली, पटना, चेन्नई और अमेठी सहित कई जगह संयंत्र लगे हैं. उत्तम गुणवत्ता और कीमत में कमी के कारण रेल यात्रियों के बीच यह पानी लोकप्रिय है. रेल यात्री इस पेय के प्रमुख उपभोक्ता हैं. इसके बावजूद रेल नीर घाटे में है, क्योंकि बड़े पैमाने पर घोटाले का जाल बुन दिया गया है. सीबीआई इस घाटे को एक सुनियोजित साजिश के रूप में देख रही है. दरअसल रेल नीर के रेल यात्री ही सबसे बड़े उपभोक्ता हैं. उन्हें ही वह जरूरत के मुताबिक पानी की आपूर्ति नहीं कर पाता है. इसीलिए रेलवे ने महाराष्ट्र के अंबरनाथ और तमिलनाडु के पालूर में नए जल उत्पादन संयंत्र लगाए हैं.

लिहाजा निजी कंपनियों की कुटिल मंशा है कि रेल नीर को येन-केन-प्रकारेण घाटे के सौदे में तब्दील कराकर सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को बाजार से बेदखल कर दिया जाए. ऐसा संभव होता है तो कंपनियों को रेल यात्रियों के रूप में नए उपभोक्ता मिल जाएंगे. पानी की गुणवत्ता बनाए रखने की शर्त खत्म हो जाएगी और तुलनात्मक दृष्टि से मूल्य संतुलित रखने के झंझट से भी छूट मिल जाएगी. ■■

तोल बोल

नीतीश कुमार रोज जनता को गुमराह करने के लिए नई-नई बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है.
■ अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष

यह चलन अत्यंत व्यथित करने वाला है कि कुछ लोग अपना नजरिया और विचार दर्ज कराने के लिए तोड़फोड़ का तरीका अपना रहे हैं.
■ अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री

इतिहास पर नजर 21 अक्तूबर

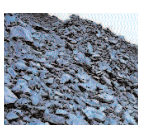

आज ही के दिन 1966 में ब्रिटेन के वेल्स क्षेत्र में एबरफैन के नजदीक की कोयला खदानों के पास खदानों से निकले कोयले के एक पहाड़ के धसकने से 144 लोग मारे गए जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे. दरअसल यह पहाड़ धसका और कुछ ही क्षणों में पास ही बने एक स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया. यह घटना स्थानीय समय के अनुसार करीब सुबह के 9.30 बजे घटी जब स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे अपनी कक्षाओं में जमा होना शुरू हुए थे. कुछ बच्चे स्कूल के बाहर मैदान में खेल रहे थे. एकदम राहत कार्य शुरू नहीं हो पाया क्योंकि घटनास्थल घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था. पर इसी घने कोहरे के कारण पास के एक गांव के 50 बच्चे स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाए और उनकी जान बच गई. इस घटना में बच गए एक दस साल के बच्चे ने बाद में बताया कि उन लोगों ने अचानक एक आवाज सुनी और उनके चारों ओर टेबल-कुर्सियां पलटने लगे, बच्चे जोर जोर से चीखने लगे. ■■

- 1805-स्पेन के तट पर ट्राफलगर की लड़ाई हुई. ब्रिटेन ने फ्रेंच और स्पेनिश बेड़े को पराजित किया.
- 1934-जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की.
- 1944-द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने जर्मन शहर ऑकिन पर कब्जा किया.
- 1945-फ्रांस में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया.
- 1950-चीनी सेना ने तिब्बत पर आक्रमण किया.

पाठकों के पत्र

रेलवे की छोटी लाइन बंद न हो

जबलपुर-नैनपुर, बालाघाट-छिंदवाड़ा-मंडला के लिए रेलवे की छोटी लाइन को क्यों बंद कर दिया गया? इस आदिवासी अंचल के बेचारे गरीब, गांववासी और शहरवासी भी इन छुक-छुक गाड़ियों में सफर करते थे. अपनी रोजी-रोटी कमाते थे. कुकड़ी-खापा के अति गरीब जंगलवासी नहीं चाहते थे कि छोटी रेलगाड़ी बंद हो. ज्ञातव्य हो कि हैदराबाद से लेकर कन्याकुमारी तक बड़ी रेल लाइन के साथ छोटी रेल लाइन भी है और दोनों का उपयोग भी होता है. इसी तरह गुजरात में भी बड़ी लाइन के साथ छोटी या मीटर गेज वाली लाइन भी है और इनका उपयोग भी बराबर हो रहा है. फिर छिंदवाड़ा-नागपुर, छिंदवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, बालाघाट तक ये छोटी लाइन क्यों बंद कर दी गई है?
■ जे.एल. सोनी, छिंदवाड़ा

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान जब से शुरू हुआ है तब से शिक्षा की गुणवत्ता कम हो गई है. मध्याह्न भोजन गुणवत्ता विहीन रहता है और छात्रों की उपस्थिति वास्तविक से अधिक दर्शाई जाती है. शिक्षकों पर लेखा-जोखा का बोझ बढ़ गया है.
■ पी.बी. पराडकर 'ललित', पांढुर्णा

हमारी-तुम्हारी प्रार्थना

उस नीग्रो लड़की की मां एक धनी अंग्रेज के यहां नौकरानी का काम करती थी. एक रोज अंग्रेज के दस वर्षीय लड़के ने नीग्रो लड़की से पूछा- "क्या तुम प्रार्थना करना जानती हो?"

"हां, बिल्कुल!" लड़की ने बड़े विश्वास के साथ सिर हिलाते हुए कहा और फिर बताया कि "बिना प्रार्थना किए तो मैं रात में सोती तक नहीं हूं."

विविध

अंग्रेज लड़के के चेहरे पर संशय का भाव दिखाई दिया. उसने फिर से प्रश्न किया- "लेकिन, क्या भगवान तुम्हारी प्रार्थना भी उतनी ही जल्दी सुन लेता है जितनी जल्दी वह हम गोरे लोगों की सुनता है?"

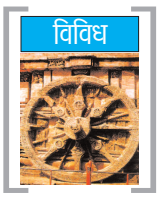

नीग्रो लड़की की समझ में नहीं आया कि वह अंग्रेज लड़के के उस सवाल का क्या जवाब दे. क्षणभर चुप रहने के बाद वह बोली, "हम अपनी प्रार्थना सीधे भगवान के कान में कहते हैं, आंखों में नहीं." ■■

© लोकमत समाचार
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
0712-2423527 (7 लाइन) : 6618555
Email : lsedit.ngp@lokmat.com
advt.ngp@lokmat.com circ.ngp@lokmat.com